International Journal of Creative Research Thoughts
Volume 2, Issue.2, Feb 2014
ISSN:-2320-2882

ORIGINAL ARTICLE

वर्तमान अर्थव्यवस्था का दंश बनाम सर्वोदय आधारित अर्थव्यवस्था

डॉ. जितेन्द्र शर्मा
एसोसियेट प्रोफेसर–दर्शनशस्त्र
महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट सतना (मप्र)

शोध आलेख– सार

प्रस्तुत शोध आलेख में भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष विद्यमान वर्तमान चुनौतियों एवं समस्याओं के उल्लेख सहित उनका गॉधीवादी समाधान प्रस्तुत किया गया है। बढ़ती मुद्रास्फीति, वैश्विक बाजार में डालर के मुकाबले भारतीय मुद्रा रूपये का निरन्तर अवमूल्यन, बेरोजगारी, बढ़ता शहरीकरण, गॉव से उपयोगी श्रम का शहरों की तरफ निरन्तर पलायन, औद्योगिक असुन्तलन, ग्रामीण जीवन की उपेक्षा आदि वर्तमान अर्थव्यवस्था की प्रमुख चुनौतियॉ एवं समस्यायें हैं। लेखकीय अभिमत है कि बापू द्वारा प्रतिपादित सर्वोदय दर्शन के आधार पर यदि हम स्वतन्त्र भारत का आर्थिक नियोजन किये होते तो अर्थव्यवस्था की वर्तमान समस्यायें न पैदा हुई होती। गॉव खुशहाल होते। गॉव आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होते, परिणाम–स्वरूप गॉवों से मानव श्रम का शहरों की तरफ पलायन रूक जाता। फलतः शहरों की अनपेक्षित वर्तमान समस्यायें– अत्यधिक जनघनत्व, वेश्यावृत्ति, पेयजल की समस्या, हरी सब्जियों एवं खाद्यान्न की समस्या, स्लिम वस्तियों एवं बालमजदूरी, न पैदा हुई होती। अर्थव्यवस्था का ढॉचागत आधार– कृषि, पशुपालन एवं कुटीर उद्योग मजबूत रहता परिणामतः अर्थव्यवस्था दीवालियेपन की तरफ न बढ़ती। नौजवानों के श्रम का सही दिशा में नियोजन होने से बेरोजगारी, आतंकवाद जैसी समस्याओं में स्वतः कमी आ जाती। सर्वोदय आधारित अर्थव्यवस्था को स्वीकार कर लेने से पूॅजी की असमानता भी समाप्त हो जाती परिणामतः पूॅजी के अन्यायपूर्ण वितरण से उत्पन्न वर्गभेद जैसी समस्या भी न पैदा होती। सार रूप में कहा जा सकता है कि हमें भोगवाद की सड़ांध– बिग बाजार और माल संस्कृति से दूर वर्तमान अर्थव्यवस्था में बापू के न्यूनतम उपभोग, समवितरण और अक्षय विकास के सिद्धान्त को सन्निवेशित करना पड़ेगा तभी जाकरके अर्थव्यवस्था की वर्तमानसमस्याओं से निजात पाया जा सकता है, परिणामतः देश एक खुशहाल एवं समृद्ध अर्थव्यवस्था वाला राष्ट्र बन सकेगा।

मेरे सपने का स्वराज्य तो गरीबों का स्वराज्य होगा। जीवन की जिन आवश्यकताओं का उपभोग राजा और अमीर लोग करते हैं, वही गरीबों को भी सुलभ होनी चाहिये, इसमें फर्क के लिये स्थान नहीं हो सकता। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि हमारे पास उनके जैसे महल होने चाहिये। सुखी जीवन के लिये महलों की कोई आवश्यकता नहीं। हमें महलों में रख दिया जाय तो हम घबड़ा जायॅ। लेकिन जीवन की वे सामान्य सुविधायें

गरीबों को भी अवश्य मिलनी चाहिये जिनका उपभोग अमीर आदमी करता है। मुझे इस बात में बिल्कुल संदेह नहीं है कि हमारा स्वराज्य तब तक पूर्ण स्वराज्य नहीं होगा, जब तक वह गरीबों को ये सारी सुविधायें देने की पूरी व्यवस्था नहीं कर देता।[1]

यंग इंडिया 26 मार्च 1931 में वर्णित बापू के उक्त विचार न केवल उनके सपनों के स्वराज्य का आदर्शात्मक खाका ही खींचते हैं बल्कि सर्वोदय आधारित अर्थव्यवस्था का, समृद्ध एवं खुशहाल गॉवों के रहस्य का, परिणामतः सबल एवं समृद्ध राष्ट्र का निरूपण भी करते हैं। परन्तु सर्वोदय आधारित अर्थव्यवस्था की विवेचना के पूर्व आइये वर्तमान अर्थव्यवस्था के दंश और उसके दुष्य परिणामों की नीर–क्षीर विवेचना करें– साथ ही इस तथ्य की भी मीमांसा करें कि वर्तमान अर्थव्यवस्था की समस्याओं का समाधान क्या सर्वोदय आधारित अर्थव्यवस्था में ढूॅढा जा सकता है अथवा नहीं? वर्तमान आर्थिक परिदृश्य पर प्रकाश डालते हुये दैनिक समाचार पत्र ''आज'' का सम्पादकीय लेख– 'वैश्विक रेटिंग एजेन्सियों द्वारा भारत सरकार को निरन्तर चेतावनी दी जा रही है कि आर्थिक सुधारों की गति में तेजी न आने की स्थिति में भारत की रेंटिग को गिराया जा सकता है। वर्तमान में भारत की रेटिंग न्यूनतम इनवेस्टमेंट ग्रेड पर है। इससे गिरने पर भारत की रेटिंग 'जंक' यानी कूड़े बराबर हो जायेगी। ऐसा होने पर विदेशी निवेशकों के पलायन की सम्भावना बनेगी। भारतीय उद्यमियों के लिये विदेशों से ऋण लेना भी कठिन हो जायेगा।[2] इसी तरह *'ध्वस्त होती भारत की अर्थव्यवस्था'* शी र्षक से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र का निम्न सम्पादकीय मानों खतरे के पूर्व की घंटी प्रतीत होता है ''भारतीय अर्थव्यवस्था में एक तरह की 'सुनामी' आ गयी है। सरकार प्रायः प्रतिदिन लोगों को आश्वस्त कर रही है कि अर्थव्यवस्था में सुधार शीघ्र आ जायेगा परन्तु आम जनता को सरकार के आश्वासन पर अब कोई भरोसा नहीं रह गया है।..... डालर के मुकाबले रूपया अपने सबसे निचले स्तर पर पहुॅच गया है, अन्तर्राष्ट्रीय रेटिंग ऐजेन्सियों ने चेतावनी दी है कि यदि डालर के मुकाबले रूपया इसी तरह से गिरता गया तो भारत की रेटिंग कम कर दी जायेगी जिसका सीधा अर्थ होगा कि जो विदेशी भारत में निवेश करना चाहते थे वह अपना हाथ रोक लेंगे। कुल मिलाकर भारत की आर्थिक स्थिति अत्यन्त ही चिंताजनक है। अब तो यह मानकर ही चलना चाहिये कि देश में एक अलिखित आर्थिक इमरजेंसी की स्थिति आ गयी है।[3]

यदि देश की वर्तमान अर्थव्यवस्था पर चिंतन करें तो हम देखते हैं कि पिछले कुछ समय से खाद्यान्नों और खाद्य तेलों की कमी एवं इनके मूल्यों में जिस तेजी से इजाफा हुआ है उससे पूरी दुनिया में डर की लहर दौड़ गई है। भारत में ही दो सप्ताहों में ही आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में 20 से 25 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। लेकिन सरकार की चिंता का विषय मूल्यबृद्धि नहीं विकास दर है। कुछ दिनों पूर्व ही वित्त मंत्री का कथन था कि देश सुदृढ़ आर्थिक धरातल पर खड़ा है। ऐसी आर्थिक सुदृढ़ता का आश्वासन किसके लिए? क्या यह आश्वासन बड़े घरानों के लिए है? आम आदमी कहां जाए? कहीं यह आश्वासन राजनीतिक चोचलेबाजी तो नहीं? किसान, मजदूर साधारण वेतनभोगी तथा गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लगभग 30 करोड़ बेरोजगार जिंदा कैसे रहें। भीषण मॅहगाई ने प्रमुख खाद्य पदार्थों आटा, चावल, दाल, तथा सब्जियों पर सबसे अधिक सितम ढाया है, साथ ही पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस तथा स्टील की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की दिन का चैन और रात की नींद उड़ा दी है।

कृषि और किसानों की अनदेखी तथा गलत नीतियों ने हरित क्रांति को निगल लिया है। पिछले पांच साल में डेढ़ लाख से अधिक किसान आत्म हत्या कर चुके हैं। इससे बड़ी कोई आर्थिक विषमता और क्या हो सकती है कि जहां पूॅजीपतियों, अधिकांश राजनेताओं और नौकरशाहों के पास पंचतारा होटल, रेस्तरां, फार्महाउस और गगनचुम्बी अट्टालिकाएं हैं वहीं देश के करोड़ों गरीबों के लिए न केवल पेट भरना ही दूभर होता जा रहा है, बल्कि वह सिर छिपाने के लिये छत के अभाव में खुले आसमान के नीचे रातें गुजारने को अपनी भाग्य का फैसला मान बैठे हैं। आज हमारे पास जो कुछ भी उपलब्ध है उसका न्यायपूर्ण वितरण नहीं हुआ है और जमाखोरों को खुली छूट मिलती रही तो वह दुःखद घड़ी दूर नहीं होगी जब देश में खाद्यान्न और पानी के सवाल को लेकर दंगे भड़क सकते हैं। अर्थव्यवस्था आधारित उत्पादन और वितरण के इस तंग हाल में सर्वोदय आधारित अर्थव्यवस्था स्वतः ही प्रासंगिक हो जाती है। जिसके माध्यम से पूज्य बापू ने स्वप्न देखा था–''एक ऐसे समाज के निर्माण का जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता, समानता और व्यक्तित्व की गरिमा की गारंटी दी जा सकेगी। जी हां, एक ऐसे खुशहाल समाज का जिसमें 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' का सिद्धान्त न चलता हो बल्कि चलता हो 'जियो और जीने दो' का सिद्धान्त इससे भी आगे बढ़कर 'दूसरों के लिये जियो का सिद्धान्त। जमाखोरों, काला बाजारियों ओर मुनाफाखोरों के इस्पाती चंगुल में दम तोड़ती अर्थव्यवस्था

को सच्चे मायने में आज दरकार है– सर्वोदय आधारित अर्थव्यवस्था की । हमें भोगवाद की सड़ांध–बिग बाजार और माल संस्कृति से दूर अर्थव्यवस्था में न्यूनतम उपभोग, समवितरण और अक्षय विकास की उस नैतिक आर्षचेतना का संचार करना होगा, जिसमें घोषणा की गयी थी–

"ईसावास्यमिदं सर्व यत्किंच जगत्यां जगत्
तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्यस्विद् धनम्"[4]

सर्वोदय का अर्थ है 'सबका उदय और सबके द्वारा उदय।' सर्वोदय सामाजिक न्याय से सम्बन्धित वह सिद्धान्त है जो धर्म, जाति, रूप, रंग, लिंग भाषा, वेशभू ा आदि बिना किसी भेदभाव के समाज के सभी लोगों के विकास या उदय को सुनिश्चित करता है। विकास की यह कहानी तब तक पूर्ण नहीं मानी जा सकती जब तक समाज के सभी वर्गों का विकास न किया जा सके, साथ ही विकास की यह प्रक्रिया तब तक पूर्ण भी नहीं हो सकती जब तक कि विकास प्रक्रिया में समाज के सभी वर्गों का योगदान न हो। एक की मृत्यु पर दूसरे का जीवन नहीं, एक के विनाश पर दूसरे का विकास नहीं बल्कि एक गिरे तो दूसरा उठाने का प्रयत्न करे। विकास की इस प्रक्रिया में अंधे और लंगड़े जैसा साहचर्य, सहयोग और सामंजस्य हो। यह तो वैदिक आर्ष चेतना की गॉधीवादी अभिव्यक्ति है– ॐ *सहनाववतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीत्मस्तु मा विद्विषवहै।।*

यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि सर्वोदय में उदय शब्द को हम मात्र अभ्युदय (भौतिक और सांसारिक समृद्धि) के अर्थ में ही नहीं लेंगे। सर्वोदय का अर्थ है– सर्वांगीण विकास। इसमें न तो भौतिकवाद की अवहेलना है और न आध्यत्मिकता की उपेक्षा। यह संन्यासवाद और भोगवाद के बीच की मध्यम प्रतिपदा है। गांधी जी का स्पष्ट मन्तव्य है कि जब तक अर्थव्यवस्था के संचालन में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का समावेश न होगा, अर्थव्यवस्था को भ्रष्टाचार और शो ाण से मुक्ति नहीं दिलायी जा सकती है। धन पैदा कर लेने के बाद समवितरण के लिये आने वाली समस्याओं से बचने का सर्वोत्तम तरीका यही है कि आर्थिक प्रणाली ही इस तरह की अपनायी जाये कि धन पैदा करने के साधनों (उपकरणों) का ही विकेन्द्रीकरण हो जाय। हमें कुटीर उद्योग और ग्रामोद्योग को बढ़ावा देना चाहिये। गॉधी जी अतिशय यान्त्रिकता को स्वीकार नहीं करते थे। मशीनीकरण उस स्तर तक नहीं होना चाहिये कि मनुष्य मशीन का गुलाम हो जाय। कोई भी आर्थिक प्रणाली जिसमें मानव श्रम का महत्व न हो, गॉधी जी को स्वीकार नहीं था। 'इस तस्वीर में उन

मशीनों के लिये कोई जगह नहीं होगी जो मनुष्य की मेहनत की जगह लेकर कुछ लोगों के हाथों में सारी ताकत इकट्ठी कर देती है। सभ्य लोगों की दुनिया में मेहनत की अपनी अनोखी जगह है उसमें ऐसी मशीनों की गुंजायश होगी जो हर आदमी को उसके काम में मदद पहुॅचाये।[5]

बापू का विचार है कि भारत जैसे विशाल देश में जहां अथाह मानव सम्पदा है, अत्यधिक मशीनीकरण मानव सम्पदा को निरर्थक कर देगी। गॉधी जी लघु उद्योगों का समर्थन दो कारणों से करते हैं– पहला यह कि बृहद्स्तरीय उद्योग एक लम्बे अर्से तक सब लोगों को रोजगार नहीं दे सकेगा। दूसरा यह कि उद्योग एवं रोजगार पर राज्य द्वारा पूर्ण एकाधिकार की स्थिति नहीं रहेगी। देश की 59–60 वर्षों की इस लम्बी आर्थिक विकास यात्रा में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हमने निःसन्देह महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की परन्तु यदि सम्पूर्ण परिदृश्य पर आलोचनात्मक दृष्टि रखी जाय तो यह कहा जा सकता है कि देश के इस आर्थिक नियोजन में कुछ मौलिक भूल हो गयी। अर्थव्यवस्था का एकांगी विकास ही हो पाया। शहर दिन–प्रतिदिन सुखी और समृद्ध होते गये जब कि गांव विकास की दौड़ में शहरों से काफी पिछड़ गये। महानगरों में बड़े–बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों और कारखानों की स्थापना की गयी इससे देश में शहरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग काम की खोज में बड़े–बडे शहरों और औद्योगिक केन्द्रों में आकर बस गये। इससे इन क्षेत्रों में न केवल जनसंख्या का बहुत अधिक घनत्व बढ़ गया बल्कि किसी भी स्थान पर बहुत अधिक लोगों के एकत्रित हो जाने से अनेकानेक कठिनाइयां उत्पन्न हो गयी। पर्यावरण प्रदूषण, मलिन बस्तियों की बृद्धि, स्वच्छ पेयजल की कमी, आवास की कमी, अत्यधिक जनघनत्व, मंहगाई, अपराधों की बढोत्तरी, देह व्यापार से लेकर मानव अंगों का व्यापार आदि ऐसी समस्याएं हैं जो आज के विकसित महानगरों की नियति बन चुके हैं। दूसरी ओर ग्रामीण आबादी तथा अर्थव्यवस्था में असन्तुलन की स्थिति पैदा हुई है। रोजगार की तलाश में लोग गांव से शहर की तरफ पयालन कर जाते हैं। इससे गांव में उत्पादक, उपयोगी मानव श्रम की कमी होती जा रही है। शहर के प्रति बढ़ता हुआ आकर्षण गांवों की वीरानगी का कारण बनता जा रहा है।

यदि हम दश की माली हालत सुधारना चाहते हैं, अर्थव्यवस्था से आर्थिक असन्तुलन को समाप्त करना चाहते हैं तो गांवों का समुचित विकास करना ही होगा। "भारत की

जरूरत यह नहीं है कि चंद लोगों के हाथों में बहुत सारी पूँजी इकट्ठा हो जाय बल्कि पूँजी का ऐसा विवरण होना चाहिये कि वह इस 1900 मील लम्बे और 1500 मील चौड़े विशालदेश को बनाने वाले साढेसात लाख गॉवों को आसानी से उपलब्ध हो सके।[6] इन ग्राम वस्तिंयों का पुनरूत्थान होना चाहिये। भारतीय गॉव, भारतीय शहरों की सारी जरूरतें पैदा करते थे और उन्हें देते थे। भारत की गरीबी तब शुरू हुई जब हमारे शहर विदेशी माल के बाजार बन गये और विदेशों का सस्ता और भद्दा माल गॉवों में भरकर उन्हें चूसने लगे।[7] गांव के विकास के लिये सर्वोदय आधारित अर्थव्यवस्था के सिवा कोई विकल्प नहीं। गांवों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिये गांव में लघु उद्योगों की स्थापना करनी ही होगी। प्रत्येक गांव को समृद्ध और खुशहाल गणराज्य के रूप में विकसित करना होगा। लघु उद्योगों की स्थापना से रोजगार मिलने के कारण लोगों की बेरोजगारी जन्य भग्नाशा, हताशा और कुंठा नहीं झेलनी पड़ेगी। परिणामस्वरूप गांव से शहरों की तरफ होने वाला श्रम का पलायन रूक जायेगा, फलतः एक तरफ गांव खुशहाल और समृद्ध होंगे दूसरी तरफ शहर अतिशय जनसंख्या से होने वाली समस्याओं से मुक्त। ग्राम स्वराज्य की मेरी कल्पना यह है कि यह एक ऐसा पूर्ण प्रजातन्त्र होगा जो अपनी अहम जरूरतों के लिये अपने पड़ोसी पर भी निर्भर नहीं रहेगा और फिर भी बहुतेरी दूसरी जरूरतों के लिये जिनमें दूसरों का सहयोग अनिवार्य होगा वह पस्पर सहयोग से काम करेगा। इस तरह हर एक गांव का पहला काम यह होगा कि वह अपनी जरूरत का तमाम अनाज और कपड़े के लिये कपास खुद पैदा कर ले। इसके अलावा उसके पास इतनी सुरक्षित जमीन होनी चाहिये, जिसमें ढोर चर सकें और गांव के बड़ों व बच्चों के लिये मन बहलाव के साधन और खेलकूद के मैदान वगैरह का बन्दोवस्त हो सके। इसके बाद भी जमीन बची तो उसमें वह ऐसी उपयोगी फसलें बोयेगा, जिन्हें बेचकर वह आर्थिक लाभ उठा सके, (लेकिन) वह गॉजा, तम्बाकू अफीम बगैरह की खेती से बचेगा।[8]

भारतीय अर्थव्यवस्था पर आतंकवाद की मार काफी भारी पड़ रही है। देश के बाहर और भीतर सक्रिय विघटनकारी और विप्लकारी शक्तियॉ बेरोजगार और बेकार पड़े युवाओं को आतंकवाद का हथियार बना रही है। सरकारी वेतन भत्तों से परेशान सरकारें, सरकारी प्रति ठान की स्थापना/निवेश से कतराने लगी हैं। विदेशी पूंजी निवेश कितनी भी सावधानी से कराया जाय उससे राष्ट्रीय उत्पादन का बहुत बड़ा भाग तो विदेश चला ही

जाता है। गांधी वादी अर्थव्यवस्था में इस समस्या का भी स्थायी निदान है। सभी हाथों को काम और सभी का रूहानी विकास यही तो है गांधी वादी अर्थव्यवस्था का मूलमंत्र। यदि इसी समतामूलक समाज की स्थापना हो जाय तो किसी भी वर्ग में न तो वर्तमान के प्रति विद्रोह का भाव होगा और न होगी भविष्य की दुश्चिंता। परिणामतः युवामन का भटकाव नहीं होगा और वे राष्ट्र की मुख्य धारा से स्वतः जुड़ जायेंगे।

गांधी जी का स्पष्ट मत है कि ग्रामीण जीवन में आर्थिक स्वावलम्बन केवल खादी और चरखे से ही संभव नहीं है। इसके लिये ग्रामवसियों को अन्य सहायक ग्रामोद्योगों को भी अपनाना पड़ेगा। पशुपालन एक ऐसा ही उद्योग है। दुग्ध उत्पादन और व्यवसाय के माध्यम से जहां ग्रामीण अपनी माली हालत में सुधार तो ला ही सकता है वहीं अपने परिवार का स्वास्थ्य भी अच्छा बना सकता है, परन्तु दुग्ध व्यवसाय के समक्ष कतिपय परेशानियां इसे व्यावसायिक स्वरूप नहीं ग्रहण करने दे रही हैं। इनमें से कुछ निम्नवत् हैं– उत्तम नस्ल के साड़ों और भैंसों की कमी–यद्यपि इस दिशा में सरकार ने ब्लाक स्तर पर कुछ सुविधायें दी हैं परन्तु एक तो गांवों से ब्लाक की दूरी और दूसरे सरकारी कर्मचारियों में अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही और उनमें व्याप्त भ्रष्टाचार सरकारी सुविधाओं का वास्तविक लाभ जनता तक पहुंचाने में बाधक सिद्ध हो रहा है। दुग्ध और दुग्ध पदार्थों के विपणन की समस्या पशुपालन को व्यवसाय के रूप में स्थापित होने में सबसे बड़ी बाधा है। यद्यपि सहकारी डेरी फार्म इस समस्या का समाधान तो है परन्तु ऐसी सहकारी डेरियॉ महानगरों, नगरों या नगरों से सटे हुये विकसित गांवों तक ही सीमित हैं, इस कारण पशुपालन व्यवसाय उद्योग के रूप में विकसित नहीं हो पा रहा है। चरागाहों की कमी और ग्रामीणों की आर्थिक तंगी भी पशुपालन की अन्य बाधायें है। इसके अलावा कुछ अन्य ग्रामोद्योग इस प्रकार है– कागज बनाना, तेल पेरना, मुर्गीपालन, कुक्कट पालन, सुअर पालन, मधुमक्खी पालन, धान से चावल निकालना, गुड़ बनाना, दियासलाई, मोमबत्ती, अगरबत्ती, बांस से जुड़े उद्योग, आचार–पापड़ मसाले बनाना आदि ऐसे छोटे–छोटे उद्योग है जो ग्रामीण आर्थिक स्वावलम्बन की रीढ़ की हड्डी सिद्ध हो सकते हैं। परन्तु उन सभी के पीछे सबसे बड़ी समस्या उत्पादित माल के विक्रय की है अर्थात् विपणन की समस्या। सरकार को इस दिशा में पूरी इमानदारी, समर्पण और पारदर्शता से कार्य करना होगा अन्यथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के ये विकल्प मुंगेरीलाल के सुहाने सपने जैसे ही बने रह जायेंगे।

यहां पर विचारणीय प्रश्न यह है कि ग्रामोद्योगों की उपयोगिता और आवश्यकता को कोई नकार तो नहीं सकता तथापि ऐसी स्थिति में इनका पर्याप्त प्रचार–प्रसार क्यों नहीं हो पाया? क्यों ये उद्योग अर्थव्यवस्था के आधारभूत ढॉचे के रूप में विकसित नहीं हो पाय? कारण स्पष्ट है। वस्तुतः स्वतन्त्रता के उपरान्त आज तक सरकारों ने ग्रामोद्योगों की स्थापना और विकास के लिये न तो इसे सरकारी योजनाओं का अंग बनाया और न इसके विकास के लिये दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कोई कार्य योजना ही प्रस्तुत की। यत्किंचित् प्रयास जो किये भी गये पुनर्समीक्षा के अभाव में वे दम तोड़ रहे है। सरकारी तन्त्र और योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार इनके विकास में सबसे बड़ी बाधा है। यदि सरकार वास्तव में इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनाना चाहती है तो नयी योजनायें बनाने से अच्छा है, पूर्ववर्ती योजनाओं को ईमानदारी से लागू किया जाय, और इसमें आ रही दिक्कतों का व्यावहारिक समाधान किया जाय।

जनता को भी आलस्य और कापुरूषता से दूर होना होगा। प्रायः गांवों में भी लोग मोटा काम नहीं करना चाहते इस दिशा में लोगों को शिक्षित और जागरूक बनाने की आवश्यकता है। स्वयंसेवी संस्थाओं की भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। देखना है आर्थिक उदारीकरण की डायलेसिस (जीवन रक्षक उपकरण) पर निर्भर देश के आर्थिक नियन्ता सर्वोदय आधारित अर्थव्यवस्था के खाद पानी का उपयोग कर पाते हैं या नही।

संदर्भ सूची

1. महात्मा गांधी– मेरे सपनों का भारत पृष्ठ सं. 22, सर्वसेवा संघ प्रकाशन राजघाट वाराणसी संस्करण सितम्बर 1995।
2. दैनिक समाचार पत्र 'आज' बुधवार 5 जून 2013।
3. दैनिक समाचार पत्र 'आज' सोमवार 02 सितम्बर 2013
4. ईशावास्योपनिषद् प्रथम मन्त्र अन्तर्गत ईशादिनौउपनिषद गीताप्रेस गोरखपुर
5. महात्मा गांधी– हरिजन सेवक (हिन्दी साप्ताहिक) 28 जुलाई 1946
6. महात्मा गांधी –मेरे सपनों का भारत पृष्ठ 32 सर्व सेवा संघ प्रकाशनराजघाट वाराणसी संस्करण सिम्बर 1995
7. महात्मा गांधी –हरिजन (अंग्रजी साप्ताहिक) 27 फरवरी 1937
8. महात्मा गांधी– मेरे सपनों का भारत पृष्ठ 33 सर्व सेवा संघ प्रकाशन राजघाट वाराणसी संस्करण सितम्बर 1995